bases and also for fishing; and if so, will Government avail of this offer to develop Okha port which is a very natural port which can then be used not only for defence purposes but also as an outlet on the west coast?

SHRI M. R. KRISHNA: Probably the Transport Minister will be able to answer this question. As far as Defence is concerned, I only say that if it cannot be done with our own resources, we might seek the assistance of some other country wherever required.

SHRI M. L. SONDHI: From our experience in 1965 on the west coast, would the Minister be prepared to tell the House that the policy of going in for aircraft carriers was misconceived, and a large amount of money could have been saved and devoted to the development of Okha as a naval base?

SHRI M. R. KRISHNA: At one time, aircraft carrier might have been considered to be too expensive, but when we see the preparations going on on the other side, specially by our enemies, I do not think any craft that the Defence Ministry today has can be considered unnecessary.

SHRI M. L. SONDHI: That was not my question.

SHRI SAMAR GUHA: Is there any declared enemy of India?

MR. SPEAKER: He ought to know.

SHRI SAMAR GUHA: He might have said 'potential enemy'.

SHRI M. R. KRISHNA: I think you, Sir, can help us to answer this question.

MR. SPEAKER: He is asking a question which is a matter of opinion which I thought I should reject. Now he does not stop there. Shrimati Sharda Mukerjee.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: When there is an air force and army complex in Okha, has the Minister considered the fact that in order to have an effective and complete defence complex, we would have to have a naval complex also? If so, why is the Ministry still considering this matter in view of the fact that there is an ever-present danger from Pakistan?

SHRI M. R. KRISHNA: The hon. lady member is an expert in defence matters. She says we have got a school there...

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: Not school. We have got an army and air force complex there.

SHRI M. R. KRISHNA: It is a co-ordination of these three wings. We have got a school where this is taught. We are alive to this.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: It is a defence complex, not a school. Why have Government not taken a decision to have a naval station also developed there?

SHRI M. R. KRISHNA: Co-ordination is perfect.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: They have opened an air force station and an army station there. Why have they not developed a naval complex also?

MR. SPEAKER: She is not asking a question, but giving a suggestion.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: It is not a suggestion.

SHRI RANJEET SINGH: Let me put it as a question.

MR. SPEAKER: Next question.

जम्मू तथा काश्मीर का विकास

*637. **श्री राम गोपाल शालवाले :** क्या **प्रधान मन्त्री** 30 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968-69 में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को 21.70 करोड़ रुपये दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस सहायता में से अधिकांश राशि को श्रीनगर पर खर्च करती है, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू के लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपमंत्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां। राज्य की वार्षिक योजना 1968-69 के लिए ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम गोपाल शालवाले : अध्यक्ष महोदय यह रुपया जो जम्मू काश्मीर रियासत को दिया जाता है, यह दोनों खण्डों के लिये दिया जाता है, लेकिन इस बात की आपत्ति बार बार इस सदन में की गई है कि यह सारा रुपया केवल काश्मीर पर ही खर्च किया जाता है, जम्मू पर खर्च नहीं किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार ने काश्मीर सरकार से क्या जवाब तलबी की है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: The hon. member is under the presumption that much more money has been spent in the Kashmir Valley than in Jammu. This is not correct. The Gajendragadkar Commission, which was appointed some time ago by the J. & K. Government, has said this in their report:

> "There does not, therefore, seem to be justification for the complaint of there having been deliberate discrimination exercised against either region".

I am just quoting a sentence from the Report to show that it is not at all a fact that more money has been spent in the Kashmir Valley.

श्री राम गोपाल शालवाले : इस बारे में प्रधान मन्त्री से कई बार शिकायतें की गई हैं, मने भी इस बारे में प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था और मेरे पत्र के आधार पर प्रधान मन्त्री ने कोहली कमीशन की नियुक्ति की थी काश्मीर में सादिक सरकार की साम्प्रदायिक नीति की जांच करने के लिये । मैं आज इस सदन में जानना चाहता हूं—प्रधान मन्त्री जी बतायें—कोहली कमीशन की रिपोर्ट उन के पास पहुची या नही, क्योंकि मेरी गवाही भी उस के सामनें हो चुकी है, 285 गवाहियां उस के सामने हुई हैं, उस रिपोर्ट को दबाने का क्या कारण है—प्रधान मंत्री जी स्वयं इस पर प्रकाश डालें ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बतायें इस से इस सवाल का क्या ताल्लुक है ?

श्री राम गोपाल शालवाले : इसी सवाल के आधार पर ही कोहली कमीशन बैठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट .....

श्री राम गोपाल शालवाले : मैं कोहली कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूं—उस को दबाने के क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस बात को पूछ चुका हूं लेकिन प्रधान मन्त्री जी इस को दबाना चाहती हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस को समर्थन दीजिये ।

MR. SPEAKER: This does not arise out of the original question. He might table a separate question.

श्री राम गोपाल शालवाले : वह जवाब देना चाहती हैं, आप क्यों रोकना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER: It does not arise out of this.

श्री राम गोपाल शालवाले : काश्मीर में साम्प्रदायिकता के आधार पर सारा काम किया जाता है—यही आधार है मेरे इस सवाल का । मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी इस का जवाब दें ।

SHRI BAL RAJ MADHOK: The question was of discrimination between two regions of Jammu and Kashmir. Here also there is discrimination.

MR. SPEAKER: The Gajendragadkar Commission's report has been quoted to disprove that.

श्री राम गोपाल शालवाले : मेरा सवाल तो कोहली कमीशन के बारे में है । इस सदन म हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

है । आप उस से हम को वंचित क्यों करते हैं [? या तो आप इस पर रूलिंग दीजिए या प्रधानमंत्री इस का जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । आप एक ऐसा मसला उठा रहे हैं जिसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है । आप ने कोई चिट्ठी लिखी किसी कमीशन के बारे में उस के लिए आप सवाल पूछना चाहते हैं .....

श्री राम गोपाल शालवाले : कमीशन बिठाया गया इस के बारे में । कमीशन ने रिपोर्ट दी। इसलिए मैं कहता हूं कि उस रिपोर्ट को दबाया गया । गजेन्द्र गडकर के बारे में मेरा कोई सवाल नहीं है । कोहिली कमीशन के बारे में मेरा सवाल है । उसके ऊपर प्रधान मन्त्री प्रकाश डालें ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । आप क्यों डिफाई करते हैं जब मैंने कहा कि इट डज नाट एराइज ।

SHRI INDER J. MALHOTRA: One of the major recommendations of the Gajendragadkar Commission was the establishment of regional and State Development Boards. May I know whether this recommendation has been fully accepted and implemented by the State Government?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): The Gajendragadkar Commission recommended the Regional Development Board; The State Government have already set up a State Development Board; and have decided to set up Regional Boards under its auspices—one for Jammu, one for Kashmir and one for Ladakh.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 1964 तक जम्मू काश्मीर राज्य में 16 सालों में 72 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से उनको सहायता दी गई थी और 1964 से 68 तक 150 करोड़ से भी अधिक सहायता दी गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पिछले चार सालों में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति जम्मू काश्मीर राज्य में पैदा हुई जो जम्मू काश्मीर राज्य के विकास के लिए 150 करोड़ से भी अधिक रुपया दिया गया और पिछले 16 सालों में केवल 72 करोड़ दिया गया ? और यह जो इतना अधिक रुपया दिया गया क्या उसी अनुपात में सड़कें या इंडस्ट्री या और दूसरी चीजों का विकास जो होना चाहिए था वह उसी अनुपात में हुआ है ? यदि नहीं हुआ है तो कौन से कारण बाधक रहे हैं और यह 150 करोड़ रुपया कौन सी खाई में जा कर पड़ गया ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: In Jammu and Kashmir the plan and non-plan expenditure during the period 1956-57 to 1965-66 is as follows. From 1956-57 to 1960-61 in the Jammu region it is Rs. 16.30 crores in the Kashmir region it is Rs. 16.26 crores.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने सवाल को फिर दोबारा समझा दूं अगर आप इजाजत दें । मेरा सवाल यह था कि 16 साल में जम्मू काश्मीर राज्य के विकास के लिये केन्द्र द्वारा 72 करोड़ रुपये दिये गये और पिछले चार सालों में 1964 से 68 तक 150 करोड़ रुपये से भी अधिक दिया गया । तो यह जो अनुपात में अन्तर है इस का आधार क्या है ? और यह जो 150 करोड़ रुपये चार वर्षों में गये तो क्या उसी अनुपात में जम्मू काश्मीर राज्य का विकास भी अधिक हुआ ? अगर अधिक विकास हुआ तो वह क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस के पूरे डीटेल्स नहीं हैं । लेकिन इस बीच में माननीय सदस्य को मालूम होगा कि वहां खाने की और चावल की कमी हो गई थी, उसके लिये अधिक देना पड़ा था और दूसरी कई चीजों पर जिनपर काम नहीं हुआ था उनपर काम भी बढ़ाया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सवाल यह है कि 16 साल में 72 करोड़ और चार साल में 150 करोड़ रुपया यह खाली कवल चावल की कमी पर ही तो नहीं हो सकता.....

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ने कहा डीटेल्स उस के मेरे पास नहीं हैं । माननीय सदस्य के लिये उन को एकत्रित किया जा सकता है ।

श्री महाराज सिंह भारती : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहली तीन योजनाओं में लद्दाख के लिये कुछ खर्च नहीं हुआ है और अब लद्दाख के लिये आप ने रीजनल डेवलपमेंट कौंसिल बनाई है तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि पिछला जो डेवलपमेंट लद्दाख में नहीं हुआ है उस को ध्यान में रखते हुए लद्दाख को विशेष रुपया दिया जाय ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY: It has been decided to spend Rs. 11.83 crores in the Ladakh region in 1968-69.

श्री महाराज सिंह भारती : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिच्छली तीन योजनाओं में कोई खर्च नहीं हुआ लद्दाख के लिये तो वहां पर अब स्पेशली ज्यादा रेशियो प्रोपोर्शन में खर्च करेंगे ? 11 करोड़ तो हम ने सुन लिया । वह तो उन के हिस्से में अब आता है, वह है । पुराना मेक अप करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्रीमति नन्दिनी सत्पथी : जी हां, इस बात को ध्यान में रख कर लद्दाख रीजन के डेवलपमेंट के लिये जो कुछ करना है वह किया जाता है । जैसा कि गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ सजेशन्स दिये गये हैं उस के ऊपर भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने जबाब में यह कहा कि चावल घट गया था काश्मीर में, उस पर आप न चावल के लिये पैसा दिया । लेकिन अब मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप एश्योरेंस दें. आप ने कहा कि डेवलपमेंट हुआ, मैं डेवलपमेंट का ब्यौरा चाहता हूं, आप आज दें या कल दें, इस का ब्यौर में चाहता हूं ।

SHRIMATI INDIRA GANDHI: What development?

श्री शिव नारायण : जवाब हम ने नहीं सुना अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष महोदय : आप ने कुछ पूछा हो तो जबाब आए ।

श्री शिव नारायण : डेवलपमेंट के बारे में मैंने पूछा ।

MR. SPEAKER: Assurances are not given in the Question Hour. It is meant for eliciting information.

Production in Ordnance Factories in West Bengal

*639. SHRI RANJEET SINGH:
SHRI NARAYAN SWAROOP SHARMA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since March, 1968, the production schedule of the Ordnance Factories situated in West Bengal has been lagging behind; and

(b) if so, whether it has adversely affected the supply position in the services?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) No, Sir. The production schedule of the Ordnance Factories situated in West Bengal has, by and large, been maintained.

(b) No, Sir.

SHRI RANJEET SINGH: First I would like to have a clarification of the words "by and large". This clarification I must have before I can ask a supplementary. He says they have been able to maintain production by and large. It means that we have not been able to maintain the target but it is touching somewhere near that. In the ordinary usage of the language the phrase means "short of target".

SHRI L. N. MISHRA: As the hon. Member has not understood the meaning of "by and large", I would like